सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाती है ।

मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि

3021. श्री गं० च० दीक्षित : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 30 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 783 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के बावजूद कि मध्य प्रदेश में गुजरात की तुलना में अधिक नलकूप हैं, मध्य प्रदेश में गुजरात की तुलना में कम भूमि की सिंचाई होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या कमी को पूरा करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश और गुजरात में राजकीय नलकूप जिनमें समन्वेषी नलकूप भी शामिल हैं क्रमश 66 तथा 649 हैं । 1965–66 के दौरान राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्रमश 8371 एकड़ और 70,475 एकड़ था। गुजरात में अधिक क्षेत्र सिंचित किया गया था क्योंकि मध्य प्रदेश की अपेक्षा इसमें अधिक नलकूप हैं । अतारांकित प्रश्न संख्या 783 के भाग (ख) तथा (ग) का उत्तर केवल समन्वेषी कूपों से सम्बन्धित है और गुजरात में समन्वेषी कूपों की संख्या कम थी, परन्तु कुल मिलाकर वहां उत्पादक नलकूपों की संख्या अधिक थी ।

बिहार को ड्रिलिंग करने के यन्त्रों की सप्लाई

3022. श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार को सप्लाई किये गये ड्रिलिंग करने के अनेक यन्त्र बेकार पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन मशीनों का प्रयोग होता रहे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय की समन्वेषी नलकूप संस्था ने लघु सिंचाई कार्यों के लिए शुरू में 7 ड्रिलिंग रिग बिहार भेजी थी । समन्वेषी नलकूप संस्था की कोई रिग बेकार नहीं है । संस्था ने हाल ही में एक और रिग को बिहार भेजा है ।

राज्य सरकार से प्राप्त अन्तिम जानकारी के अनुसार इस समय 111 रिगें पीने के पानी की योजनाओं पर कार्य कर रही हैं तथा 14 रिगें कार्य के स्थान पर पहुंच गई हैं ताकि शीघ्र ही काम शुरू किया जा सके ।

Tourist Centre at Gwalior

3024. Shri Atam Das: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a tourist centre at Gwalior in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the venue of the Centre and the time by which the proposed centre will be set up?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No Sir. The Government of India has no such proposal.

(b) Does not arise.

Nicobarese working as Stevedores in Andaman and Nicobar

3025. Shri R. K. Sinha: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) the number of tribal Nicobarese working as stevedores in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;

(b) whether wages and other concessions applicable to the Andaman Labour Force Stevedoring Gang are being given to them;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) if so, the rates of wages and other concessions?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) The Nicobarese are engaged in stevedoring work only in Car Nicobar. Their number depends on the volume of work on each day. Generally one hundred to one hundred and fifty labourers are employed when a ship is in Port.

(b) and (c). Wages and other concessions agreed to by the tribal chiefs in Car Nicobar are being given to the Nicobarese stevedore workers. They do not get the pay and other concessions applicable to the Andaman Labour Force stevedore workers, as their conditions of work are different and they are not paid regular time scale of pay as drawn by the Andaman Labour Force stevedore workers.

(d) Does not arise.

Stock of Timber in Andaman and Nicobar Islands

3026. Shri R. K. Sinha: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total quantity of timber stock piled at present in various Departments and mill-yards of the Andaman and Nicobar Islands;

(b) the quantity of timber shipped to the mainland during 1966-67;

(c) whether an offer was made by a private firm in October, 1966 to the Andaman Administration for the purchase of 2,000 tons of timber at f.o.b. price at Port Blair;

(d) whether the offer was accepted; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) A total quantity of 11,093 tons of timber was stockpiled at the end of May, 1967, in various Depots and mill yards of the Andaman and Nicobar Islands.

(b) A quantity of 15,283 tons of timber was shipped to the main land during 1966-67.

(c) to (e). No offer for purchase of 2000 tons of timber at f.o.b. price at Port Blair was made by any private firm in October, 1966. However, an offer for purchase of certain species of timber, *viz.* Gurjan, Pandauk and a small quantity of other ply logs upto a total quantity of 2000 tons at f.o.b. rates was received in January, 1967, from Messrs. Vaid and Sons, Calcutta. Their offer was not accepted mainly on the ground that this firm is not entitled to ply logs at f.o.b. rates. The firm was informed by the Chief Commissioner, Andaman Administration to obtain its requirements, if necessary, by competing in the open auctions conducted in the Andaman Government Timber Depots at Calcutta and Madras.

भारतीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पूसा (बिहार) में कीटनाशक दवाइयों का गलत प्रयोग

3027. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पूसा (बिहार) में पैदा होने वाले धान का प्रयोग बीज के रूप में न हो कर खाद्य के रूप में किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार के अनुसंधान केन्द्र में संकर मक्का की खेती के लिये उस समय किये जा रहे कीटनाशक दवाइयों के गलत प्रयोग के कारण फसल नष्ट